

**भारत सरकार**  
**रक्षा मंत्रालय**  
**रक्षा उत्पादन विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या 569**  
**16 सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए**

**रक्षा क्षेत्र में एमआरओ केन्द्र**

**569. प्रो. अच्युतानंद सामंत :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकार भारत को रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण, अनुरक्षण और ओवरहॉल (एमआरओ) केन्द्र बनाने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या पहले की गई और रियायतें प्रदान की गई हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;
- (ख) क्या सरकार की ऐसे केन्द्रों में निवेश करने के लिए एचएएल और एमडीएल शिपयार्ड को शामिल करने की कोई योजनाएं हैं ताकि सरकारी निवेश में सहायता मिल सके और "मेक इन इंडिया" उत्पादों का और अधिक उत्पादन किया जा सके ; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)**

(क) से (ग): अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहॉल (एमआरओ) क्षेत्र में एयरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख केन्द्र के रूप में कार्य करने की क्षमता है ।

जीएसटी संरचना में हाल में किए गए यौक्तिकीकरण से भारत के अंदर एमआरओ गतिविधियां सुकर होने की संभावना है ।

एचएएल सहित काफी संख्या में सार्वजनिक तथा निजी एमआरओ सुविधाएं हैं जो देश के अंदर सैन्य एवं वाणिज्यिक एयरोस्पेस क्षेत्र की जरूरतों को पूरा कर रही हैं ।

यह क्षेत्र संघटक उद्योग के लिए अवसर भी प्रदान करेगा और इनकी सक्रिय भागीदारी प्रमुख प्लेटफार्मों की लाइफ-साइकिल सपोर्ट को सक्षम बनाएगी ।

\*\*\*